IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उच्च शिक्षा एवं संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य–4 पर एनईपी–2020 का एक अध्ययन"

ज़ोया, शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

प्रभात रंजन सिंह, शोधार्थी, राजनीतिशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

शोध सार

वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए भारत में एक नई शिक्षा नीति को अपनाने और लागू करने में काफी समय लग गया । वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा शुः की गई नई शिक्षा नीति एक स्वागत योग्य बदलाव है और इसे एनईपी : 2020 के रूप में संक्षिप्त किया गया है। शैक्षिक संरचना, दिशानिर्देश और इसके कार्यान्वयन की पद्धति सराहनीय है। असंगठित और अवैज्ञानिक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में एनईपी : 2020 द्वारा प्रस्तावित और कार्यान्वित किए गए परिवर्तन अधिक प्रतिभाशाली और अधिक व्यावहारिक छात्रों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने में आशा की एक नई लहर जगाते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विपरीत एनईपीदृ 2020 13–18 के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक लंबे छात्र–शिक्षक संबंध को प्रोत्साहित करता है, जिससे छात्रों को बेहतर स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रशंसा हासिल करने के लिएभागीदारी को बढ़ावा मिलता है। एनईपीदृ2020 स्कूल स्तर के साथ–साथ कॉलेज स्तर पर भी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता दिख रहा है। यह लेख मुख्य रूप से एनईपी : 2020 की कुछ उल्लेखनीय और मुख्य विशेषताओं और भारत में उच्च शिक्षा पर इसके परिणामों पर केंद्रित है।

मूल शब्दः नई शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, सतत विकास

परिचय–

भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने लोगों के बीच इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा प्रणाली को समाहित करती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों में भी छात्रों को उपयुक्त रूप से समायोजित करती है। शिक्षा पर पहली आधिकारिक और संरचित राष्ट्रीय नीति वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधान मंत्री कालमें लागू की गई थी। शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति वर्ष 1986 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रधान मंत्री रहते हुए भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। शिक्षा पर उपर्युक्त राष्ट्रीय नीतियों की कमियों के कारण,वर्तमान प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020 लागू की। एनईपी : 2020 प्रारंभिक, उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करने वाला एक व्यापक ढांचा है। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100: सकल नामांकन अनुपात हासिल करने और वर्ष 2040 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लक्ष्य के साथ ग्रामीण भारत के साथ–साथ शहरी भारत में भीएनईपी : 2020 का लक्ष्य शिक्षा पर राज्य के खर्च को बढ़ाना है। भारत की जी.डी.पी. मौजूदा 4: से बढ़कर 6: हो गई है। जब भारत के राज्यों की बात आती है, तो बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाएँ एनईपी : 2020 को लागू करने में बाधा बन जाती हैं।

एनईपी : 2020 के लिए जमीनी कार्य जनवरी 2015 में शुः हुआ जब पूर्व कैबिनेट सचिव श्री टी. एस. आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समितिकी स्थापना की गई थी। इस समिति ने जून 2017 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के आधार पर एनईपी : 2020 का एक मसौदा 2019 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. कृष्णास्वामीकस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक प्रतिष्ठित पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 484 पृष्ठों का मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020जारी किया गया और साथ ही सार्वजनिक बहस और सार्वजनिक परामर्श का आह्वान किया गया। लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6000 शहरी स्थानीय निकायों और 676 जिलों से 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए।

एनईपी : 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति : 2020) एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो अपने छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके राष्ट्र को एक समतापूर्ण और ज्ञानपूर्ण समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। एक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से ऐसे व्यक्तियों का विकास होना चाहिए जो विचारशील और रचनात्मक हों। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को हमेशा एक व्यक्ति को रुचि के एक या अधिक क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाना चाहिए और इस प्रक्रिया में चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। इसमें अभी भी बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, लीक से हटकर सोचने, रचनात्मक होने और योगदान और सेवा की भावना विकसित होनी चाहिए। इसे छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भी तैयार करना चाहिए जिसमें कला, खेल, भाषा, विज्ञान, मानविकी, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक विषय शामिल हैं। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य हर जिले में या उसके निकट स्थान पर कम से कम एक विश्वविद्यालय या कॉलेज स्थापित करना, पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या का पुनर्गठन करना, रचनात्मक मूल्यांकन करना, बेहतर छात्र अनुभव के लिए सहायता प्रदान करना, प्रभावी "बीज अध्ययन" का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों मेंवर्तमान शिक्षा प्रणाली में भारतीय उच्च शिक्षा के समक्ष कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं। इनमें से एक प्रमुख है "योग्यताओं का जबरन पृथक्करण, "प्रारंभिक विशेषज्ञता और छात्रों द्वारा अपने अनुसंधान क्षेत्रों का दायरा कम करना, स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान के लिए बहुत कम या कोई प्रोत्साहन नहीं, और सहकर्मी–समीक्षित शैक्षणिक अनुसंधानकानिम्न स्तर, तथा स्नातक शिक्षाके लिए धन की कमी। इसलिए, एनईपी : 2020 ने "उच्च शिक्षा के विखंडन" को समाप्त करने के लिए शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और समेकन के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और यह सुनिश्चित किया है कि यहव्यावसायिक प्रशिक्षण सहित उच्च शिक्षा में, 26.3: (2018) से 2035 तक 50: तक बहु–विषयक और अभिनव छात्रों को विकसित करने और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने में परिवर्तित हो। छात्रों की मानसिक, सामाजिक, शारीरिक क्षमताओं में सुधार के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता के तत्व के साथ एक बहु–विषयक शिक्षा समय की आवश्यकता है। लंबे समय तक शिक्षा का ऐसा व्यापक मॉडल सभी स्नातक कार्यक्रमों और सभी विषयों में उच्च कार्यक्रमों के लिए शिक्षा की पद्धति होगी।

साहित्य की समीक्षा

डॉ. कुलदीप कौर जुनेजा ने एनईपीरू2020– 21वीं सदी में नवाचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी शीर्षक वाले पेपर में पेज 201–212 के बीचने निष्कर्ष निकाला है कि शिक्षण और सीखने में प्रभावी नवाचारों के लिए एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण आवश्यक है।

गीता मनीषी स्वामी और अन्य ने अपने लेख में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयनः भगवद गीता से शिक्षाशास्त्र पर एक परिप्रेक्ष्य शीर्षक दिया है निष्कर्ष निकाला है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ श्रीमद्भागवत गीता से शिक्षाशास्त्र के संबंध में सीख लेकर एनईपी 2020 को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है, जो अभी भी समय से आगे है। इसका तात्पर्य यह है कि एनईपी–2020 द्वारा निर्धारित नई शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, शिक्षण के शैक्षणिक पहलू पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है, जिसे भगवद गीता से अपनाया जा सकता है। यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जहां एनईपी–2020 के शिक्षाशास्त्र पहलू पर भगवद गीता से निष्कर्ष और प्रासंगिकता निकालते समय डेस्कटॉप और हेर्मेनेयुटिक्स विश्लेषण के मिश्रण का उपयोग किया गया है, जो इसके सफल कार्यान्वयन और भविष्य के अध्ययनों के लिए भी आधार बन सकता है।

रजनी कांत दीक्षित–राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 : शिक्षक शिक्षा में अवसर और चुनौतियाँ– पृष्ठ 139 : 147 के बीच, निष्कर्ष एनईपी–2019 में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाकर सभी के लिए मानक शिक्षा का सुझाव दिया गया है जो भारतीय विशेषताओं में गहराई से निहित है और भारत को एक विश्वव्यापी सूचना शक्ति के रूप में पुनर्निर्माण करती है। षलिबरलआट्र्स एजुकेशनष के माध्यम से शिक्षा में अंतर अनुशासनात्मक सहयोग का निर्माण एक स्वागत योग्य इरादा है। एनईपी2020 ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक–शिक्षा के लिए सिफारिश की है लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इसे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और कितना लागू किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है

1. सतत विकासलक्ष्य 4 में एनईपी 2020योगदान को समझना
2. नई शिक्षा नीति–2020 का उच्च शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव एवं प्रभाव का अध्ययन करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह शोध एक वर्णनात्मक अध्ययन है। आवश्यक डेटा द्वितीयक स्रोतों, जैसे सरकारी वेबसाइटों, प्रसिद्ध पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों से एकत्र किया गया था। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसी डेटा का विश्लेषण और समीक्षा की गई।

एनईपी–2020 के महत्वपूर्ण घटकः उच्च शिक्षा

एनईपी–2020 के "मौलिक सिद्धांत" ऐसे व्यक्तियों को विकसित करने की परिकल्पना करते हैं जो अपने परिवार, समाज और देश के प्रति जिम्मेदार हों। ऐसा करने के लिए, इसने प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को पहचानने, और उनका पोषण करने पर जोर दिया है। इसकी योजना माता–पिता के साथ–साथ शिक्षकों को भी छात्र की प्रतिभा, क्षमता, योग्यता और दृष्टिकोण की पहचान करने और उसका पोषण करने तथा शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में छात्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील बनाने की है। इसका उद्देश्य ग्रेड 3 तक सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। इसे कला और विज्ञान, शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर विषयों जैसे विषयों के बीच कोई कठिन अलगाव के बिना सीखने के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदानुक्रम को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इसका उद्देश्य कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, खेल आदि जैसे पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में एक बहु–विषयक और समग्र शिक्षा प्रदान करके एक बहु–विषयक दुनिया विकसित करना है। यह रटने और केवल परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर भी जोर देता है। इसका उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक होने और सोच में आलोचनात्मक होने के लिए प्रोत्साहित करना है जो उन्हें तार्किक निर्णय लेने और नवाचार में मदद करता है। इसका उद्देश्य सामाजिक जीवन में नैतिकता स्थापित करना, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों का विकास करना और सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान रखना है। यह वैज्ञानिक स्वभाव, उदारीकरण, जिम्मेदारी, समानता, बहुलवाद और न्याय विकसित करने पर भी जोर देता है। इसने शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति की पहचान की है और बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया है। यह टीम वर्क और लचीलापन जैसे जीवन कौशल विकसित करने के साथ–साथ संचार और सहयोग जैसे कौशल विकसित करने पर भी जोर देता है। यह "योगात्मक मूल्यांकन" के मुकाबले सीखने के लिए समय पर "रचनात्मक मूल्यांकन" पर

भी जोर देता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह समाज में वर्तमान "कोचिंग" संस्कृति को जन्म देता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कई छात्र वंचित रह जाते हैं।

एनईपी : 2020 छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का प्रस्ताव करता है जो भाषा की बाधाओं को दूर करने और शैक्षिक योजना और प्रबंधन में सुधार करने में मदद करेगा। भारत में विविधता के प्रति उचित सम्मान के साथ, एनईपी : 2020 सभी पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ को शामिल करने को प्रोत्साहित करता है, यह ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है,एनईपी : 2020 अपने सभी शैक्षिक निर्णयों में पूर्ण समानता और समावेशन सुनिश्चित कर रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी छात्र नई शिक्षा प्रणाली में सफल होंगे। इसने "प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा" सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यक्रम को समन्वित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है।

एनईपी : 2020 की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि इसमें शैक्षणिक प्रणाली की ऑडिटिंग और सार्वजनिक प्रकटीकरण का एक सरल लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा है जो अखंडता, पारदर्शिता, साथ ही संसाधन दक्षता सुनिश्चित करता है और साथ हीस्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम सेनवाचार और आउट–ऑफ–द–बॉक्सको प्रोत्साहित करता है। यह उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए "अनुसंधान" को एक अनिवार्य शर्त के रूप में अत्यधिक महत्व दे रहा है। इसने शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और समय पर मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा प्रणाली की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए एक प्रोटोकॉल भी निर्धारित किया है। एनईपी : 2020 का उद्देश्य समृद्ध, विविध, प्राचीन और आधुनिक संस्कृति तथा ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं के बारे में शिक्षा प्रदान करके अपने छात्रों में भारत कीजड़ता और गौरव की अवधारणा को स्थापित करना है।

कुल मिलाकर, एनईपी : 2020 शिक्षा को एक सार्वजनिक सेवा मानता है, सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच मिलनी चाहिए और इसे हर बच्चे का बुनियादी अधिकार माना जाना चाहिए, और इस उद्देश्य को साकार करने के लिए, एनईपी : 2020"निजी परोपकारी और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एक मजबूत और जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमें पर्याप्त निवेश को प्रोत्साहित करता है।"

उच्च शिक्षा पर एनईपी का प्रभाव

उच्च शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य पेशेवर और व्यावसायिक शिक्षा सहित एक एकीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली बनना होगा। एनईपी 2020 अब से 4 कार्यक्षेत्रों के साथ काम करेगा; राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी); राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी); उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी); सामान्य शिक्षा परिषद (जीईसी), भारत में एचईआई को विनियमित करने के लिए, और विनियमन, मान्यता, वित्त पोषण और अकादमिक मानक सेटिंग और भारत के उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के कार्यों को अलग करने के लिएइन कार्यक्षेत्रों को शिक्षा मानकों में एकरूपता लाने के लिए तैयार किया गया है। हालाँकि, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही छतरी के नीचे लाने और शिक्षा संस्थानों के बीच गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, अनुसंधान, प्लेसमेंट, शैक्षणिक उत्कृष्टता, उद्योग लिंकेज आदि जैसे विभिन्न मापदंडों के आधार पर मापा जाना चाहिए। यदि उच्च शिक्षा आयोग इसे प्रबंधित करें, तो लाभ दूर–दूर तक फैलेगा।

श्री अतुल खोसला , अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि श्भारत को एनईपी 2020 के सपनों को पूरा करने के लिए अगले 15 वर्षों में लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (2019 में हमारी जीडीपी का लगभग आधा) निवेश करने की आवश्यकता होगी। इससे एचईआई का अति–नौकरशाहीकरण और अति–नियमन होगा

शिक्षाविदों के अनुसार, शिक्षा नीति को सुव्यवस्थित करने के लिए हमेशा एक प्रमुख निकाय की आवश्यकता होती थी। उच्च शिक्षा के लिए एक प्रमुख निकाय के रूप में, एनईपी 2020, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर, एचईसीआई (भारत का उच्च शिक्षा आयोग) स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इस प्रस्ताव ने यूजीसी और एआईसीटीई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एनईपी : 2020, अपने विधेयक में एचईसीआई को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जहां उच्च शिक्षा क्षेत्र के शैक्षणिक और वित्त पोषण पहलुओं को अलग किया जाएगा।

एनईपी 2020 और सतत विकास लक्ष्य 4

यह नीति एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके विनियमन और शासन सहित शिक्षा संरचना के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है, जो भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों पर निर्माण करते हुए एसडीजी–4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षा लक्ष्यों के अनुरूप है।"

भारत की नई शिक्षा नीति 2020

एसडीजी–4 वह लक्ष्य है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी लड़कियां और लड़के 2030 तक मुफ्त प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा पूरी करें। इसका उद्देश्य किफायती व्यावसायिक प्रशिक्षण तक समान पहुंच प्रदान करना और उच्च शिक्षा गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के उद्देश्य से लिंग और धन असमानताओं को खत्म करना है।

निम्नलिखित क्षेत्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर एसडीजी–4 के अनुरूप हैं–

- गुणवत्तापूर्ण पूर्व–प्राथमिक शिक्षा तक समान पहुंच;
- किफायती तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तक समान पहुंच;
- वित्तीय सफलता के लिए प्रासंगिक कौशल वाले लोगों की संख्या बढ़ाएँ;
- प्राथमिकशिक्षा में भेदभाव खत्म करना
- सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता।

श्री कस्तूरीरंगन के शब्दों में, "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना, जिससे एसडीजी–2030 में सूचीबद्ध पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभ्य काम करना एनईपी–2020 का जोर है," . इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि व्यावसायिक शिक्षा को स्नातक शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

परिणाम

1. भारत सरकार ने एनईपी : 2020 में एक भाषा नीति निर्धारित की है जो एक "व्यापक दिशानिर्देश" है और साथ ही प्रकृति में "सलाहकारात्मक" है। यह राज्यों और वहां की संस्थाओं पर निर्भर है कि वे अपने–अपने राज्यों में एनईपी–2020 को लागू करने के तरीके पर निर्णय लें। कर्नाटक राज्य चालू वर्ष से एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर रहे हैं।

2. एनईपी 2020 प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के क्षेत्रों में बड़े बदलाव लाता है, जिसमें प्री–स्कुलींगवर्ष को फोकस में लाया गया था।

3. यह नीति बेहतर शिक्षा और रोजगार की तैयारी के लिए बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति और कई विकास बिंदुओं पर केंद्रित है।

4. देश में बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना की घोषणा अधिक आशा जगाती है, जो आईआईटी और आईआईएम के बराबर काम करेगी और शिक्षा के प्रति बहु–विषयक दृष्टिकोण प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखेगी।

5. एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी भ्म्ए में स्नातक और फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में काम करेगी।

6. एनईपी–2020, विदेशी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और छात्रों को भारत में आने की अनुमति देकर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का द्वार खोलता है और यह घरेलू शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती है।

7. एनईपी 2020 का एक मुख्य घटक 'सशक्तिकरण और नवाचार करने की स्वायत्तता' है। कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का मुख्य जोर अनुसंधान–गहन और शिक्षण–गहन पर है।

8. अब नए बिल के मुताबिक भ्म्ब् को कोई वित्तीय शक्तियां नहीं दी जाएंगी. फंडिंग प्रक्रिया यूजीसी द्वारा नियंत्रित की जाएगी और सीधे शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आएगी।

निष्कर्ष

एनईपी–2020 निस्संदेह भारत की शिक्षा प्रणाली में स्थिरता लाने की परिकल्पना में से एक है। यह विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों को विकसित करने की आवश्यकता को उपयुक्त रूप से संबोधित करता है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के साथ भारत ने कौशल आधारित शिक्षा और नियामक ढांचे, मान्यता, वित्त पोषण इत्यादि पर अधिक स्पष्टता का मार्ग प्रशस्त किया है, जो अनुसंधान और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर फोकस वाले क्षेत्रों के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास की ओर ले जाता है। आसान निकास प्रणाली नेविद्यार्थियों को बहु–विषयक विशेषज्ञता और रोजगार के लिए तैयार होने को बढ़ावा दिया है।

संदर्भ

1. नंदिनी, एड., (29, जुलाई 2020)रू ”नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएंरू – स्कूल और उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। –हिन्दुस्तानटाइम्स
2. Https://www.researchgate.net/publication/343584099_SDG’S_AND_INDIA’S_NATIONAL_EDUCATION_POLICY_2020
3. https://research.lpubatangas.edu.ph/wp-content/uploads/2021/09/Recent-Research-andInnovation-An-Integrated-Approach.pdf#page=201
4. https://www.researchgate.net/profile/Badrilal-Gupta.
5. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP.pdf
6. डॉ. कुलदीप कौर जुनेजा ने एनईपीरू2020– 21वीं सदी में नवाचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी शीर्षक वाले पेपर में पेज 201–212 के बीच